nwda.gov.in

जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भारत का योगदान विकसित देशों से ज्यादा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत ने जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए 2022 में जलवायु वित्त में 1.28 अरब डालर का योगदान दिया है। बहुपक्षीय विकास बैंकों के माध्यम से किया गया भारत का योगदान कुछ विकसित देशों के योगदान से भी .ज्यादा है। ब्रिटेन स्थित थिंक टैंक ओडीआइ और ज्यूरिख क्लाइमेट रेजिलिएंस अलायंस के विश्लेषण में कहा गया है कि सिर्फ 12 विकसित देशों ने 2022 में अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त में अपना उचित हिस्सा दिया है। इनमें नार्वे, फ्रांस, लक्जमबर्ग, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, स्विटजरलैंड, जापान, नीदरलैंड, आस्ट्रिया, बेल्जियम और फिनलैंड जैसे देश शामिल हैं।

शोधकर्ताओं का कहना है कि जलवायु वित्त में महत्पपूर्ण कमी का कारण अमेरिका का अपने उचित हिस्से का योगदान न करना है। वहीं,

1.28 अरब डालर का योगदान भारत ने दिया 2022 में

- सिर्फ 12 विकसित देशों ने जलवायु वित्त में दिया है उचित हिस्सा
- अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने नहीं निभाया 100 अरब डालर वार्षिक योगदान का किया गया वादा

आस्ट्रेलिया, स्पेन, कनाडा और ब्रिटेन ने भी इस मोर्चे पर उम्मीद से खराब प्रदर्शन किया है। विश्लेषण में शीर्ष 30 .उच्च आय वाले और औद्योगिक रूप से विकसित देशों की पहचान की गई, जिन्होंने 2022 में विकासशील देशों को पर्याप्त जलवायु वित्त प्रदान किया है।

इस समूह में पोलैंड और रूस जैसी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं,जो मौजूदा समय में संक्रमण काल से गुजर रही हैं। चीन ने बहुपक्षीय बैंकों के माध्यम से 2.52 अरब डालर, ब्राजील ने 1.35 अरब डालर, दक्षिण कोरिया 1.31 अरब डालर और अर्जेंटीना ने 1.01 अरब डालर का योगदान दिया है।

विकसित देशों ने 2009 में कोपेनहेगन में हुई जलवायु वार्ता काप 15 में सामूहिक रूप से 2020 तक सालाना 100 अरब डालर जलवायु वित्त में योगदान करने का वादा किया था। यह रकम जलवायु परिवर्तन रोकने और और इसके प्रभाव से निपटने में विकासशील देशों की मदद के लिए है।

मानसून की अनिश्चितता से कम समय में हो रही अधिक बरसात : सीईईडब्ल्यू

संजीव गुप्ता • जागरण

नई दिल्ली : काउंसिल आन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर (सीईईडब्ल्यू) के विश्लेषण में सामने आया है कि मानसून लगातार अनिश्चित हो रहा है। छोटी-छोटी अवधि में भारी वर्षा हो जाती है। ऐसे में शहरी विकास को जल-संवेदनशील होना चाहिए। मौजूदा वेटलैंड्स व जलाशयों को पुनर्जीवित करने व ठोस कचरा प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए।

सीईईडब्ल्यू के सीनियर प्रोग्राम लीड नितिन बस्सी कहते हैं, भारत के विभिन्न हिस्सों बिहार, गुजरात, असम व दिल्ली में आई बाढ़ या जलभराव बीते 30 वर्षों की तुलना में इस जुलाई-अगस्त में हुई अधिक वर्षा व उसकी सघनता का नतीजा कहा जा सकता है। बाढ़ या जलभराव के प्रभावों को बढ़ाने वाले कारण हैं - भू-उपयोग परिवर्तन का कमजोर विनियमन, प्राकृतिक जल निकासी में व्यवधान, बढ़ते निर्माण क्षेत्रों से उच्च जल प्रवाह, बरसाती नालों का कमजोर डिजाइन, ठोस कचरा प्रबंधन नीतियों का अप्रभावी क्रियान्वयन, जो जलाशयों को बंद करता है। इसके समाधानों में बाढ़ के उच्चतम प्रवाह व मात्रा के आकलन के लिए क्षेत्रों या शहरों का नए सिरे से हाइड्रोलाजिकल अध्ययन, प्रमुख हाट स्पाट की पहचान, जल निकासी का पुनर्व्यवस्थापन जैसे उपाय शामिल हैं।